मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना

उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना (MYUVY) की घोषणा की।

उद्देश्य

- यह योजना राज्य में **युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए आधार का काम करेगी**, जिसका लक्ष्य अगले 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक नौकरियों के बजाय उद्यमिता और स्वरोजगार की ओर झुकाव रखने वाले युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना तथा राज्य में प्रतिवर्ष एक लाख नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना को सुगम बनाना है।

प्रमुख विशेषताए:

- सूक्ष्म उद्यमों और स्वरोजगार के लिए नए अवसर पैदा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना लागू की जा रही है।
- **ब्याज मुक्त ऋण:** योजना के तहत पहली किस्त में **5 लाख रुपये तक** का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, और दूसरी किस्त में युवा उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
- **वित्तीय अनुदान:** इस योजना के तहत प्रतिवर्ष एक लाख युवाओं को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
- **लक्ष्य:** महत्वाकांक्षी लक्ष्य अगले दशक में **10 लाख युवाओं को सूक्ष्म उद्योगों और स्वरोजगार से जोड़ना है,** जिससे अंततः 50 लाख से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- इस योजना को **मिशन मोड** में क्रियान्वित किया जाएगा, जिसमें जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई इसकी देखरेख करेगी, राज्य स्तर पर राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई तथा उच्च स्तर पर राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति और राज्य स्तरीय शासी समिति इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी।
- **पात्रता**: उत्तर प्रदेश के **21 से 40 वर्ष** की आयु के निवासी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं। इस योजना के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता **आठवीं कक्षा या समकक्ष योग्यता** उत्तीर्ण होना है। कौशल-संबंधी प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या डिग्री रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- **समग्रता**: इस योजना में सामान्य श्रेणी के अतिरिक्त **महिलाओं, दिव्यांगजनों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग** के व्यक्तियों द्वारा उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता हेतु अनुदान का प्रावधान शामिल है।

अयोध्या किलाबंदी

अयोध्या में भगवान राम के भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार शहर को उन्नत उच्च तकनीक सुरक्षा उपायों से सुदृढ़ कर रही है।

प्रमुख बिंदु

- व्यापक सुरक्षा योजना में अयोध्या को सीसीटीवी की व्यापक निगरानी में रखना शामिल है, जिससे तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और स्वच्छता दोनों सुनिश्चित हो सके।
- यह प्रणाली अधिकारियों को कमांड और कंट्रोल सेंटर से संदिग्धों पर नज़र रखने की अनुमति देती है, साथ ही चौराहों और सड़कों पर नगर निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली बुनियादी सुविधाओं पर भी नज़र रखती है।

- ‘सेफ सिटी’ परियोजना के तहत शहर की सुरक्षा और निगरानी प्रणाली को लागू करने की जिम्मेदारी एलाइड डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड को सौंपी गई है, जिसकी परियोजना की लागत 8.49 करोड़ रुपये है।

यूपी जीएसवीए लक्ष्य

यूपी सरकार ने अपने जीएसवीए लक्ष्य का 101% हासिल कर लिया है।

प्रमुख बिंदु

- **उपलब्धि**: उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने के अपने मिशन में, यूपी सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने जीएसवीए लक्ष्य का 101% हासिल करके उम्मीदों को पार कर लिया है।
- केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित एक रिपोर्ट में इस उपलब्धि को उजागर किया गया, जो उत्तर प्रदेश को औद्योगिक महाशक्ति बनाने के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।

क्षेत्रवार उपलब्धियां

- वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न क्षेत्रों में सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई।
- **परिवहन, भंडारण और संचार** क्षेत्रों में सबसे अधिक 129% जीएसवीए दर्ज किया गया है।
- राज्य ने कृषि, खनन, निर्माण, परिवहन और रियल एस्टेट क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है।
  - **कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों** ने 5.98 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य हासिल किया, जो 5.85 लाख करोड़ रुपये से अधिक है तथा 102% तक पहुंच गया।
  - **खनन एवं उत्खनन क्षेत्र** ने 0.30 लाख करोड़ रुपये का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जो 0.26 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य से अधिक तथा 115% तक पहुंच गया।
  - **निर्माण क्षेत्र** में 2.79 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जो 2.48 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य से 112% अधिक है।
  - **परिवहन, भंडारण और संचार** क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई, जो 1.98 लाख करोड़ रुपये रही, जो इसके 1.53 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य का 129% है।
  - रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपने लक्ष्य का 102% हासिल कर लिया है। लक्ष्य 3.23 लाख करोड़ रुपये था, और सेक्टर ने 3.29 लाख करोड़ रुपये हासिल किए।
- इसके अलावा, सरकार के प्रयासों से विनिर्माण, ऊर्जा, व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्तरां, वित्तीय सेवाएं, लोक प्रशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में भी आशाजनक परिणाम सामने आए हैं।
- विशेष रूप से द्वितीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसने अपने लक्ष्य का 104% हासिल किया है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र में 103% की वृद्धि हुई है। तृतीयक क्षेत्र ने भी पर्याप्त प्रगति दिखाई है, जो लगभग 11 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया है।

जीएसवीए एक प्रमुख **आर्थिक उत्पादकता मीट्रिक** है जो अर्थव्यवस्था और उसके उत्पादक क्षेत्रों में राज्य के योगदान का मूल्यांकन करता है।

यह **विभिन्न क्षेत्रों में निजी खपत**, सकल निवेश, सरकारी निवेश और व्यय, कुल निर्यात और आयात, तथा कुल उत्पाद कर और सब्सिडी का आकलन करता है।

प्रधानमंत्री की पोलैंड और यूक्रेन यात्रा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड और यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्रा।

प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड पहुंचे हैं, जो 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा है।
- भारत और पोलैंड अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
- पोलैंड की यात्रा करने वाले अंतिम भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, जिन्होंने 1979 में पोलैंड की यात्रा की थी।
- उनकी यात्रा में पोलैंड और यूक्रेन दोनों जगह रुकना शामिल है, जिसमें वारसॉ उनका पहला गंतव्य है और यूक्रेन की राजधानी कीव उनकी दो देशों की यात्रा का दूसरा पड़ाव है।
- भारत और पोलैंड ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते पर सहमति जताई है, जिससे नई तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।

लघु समाचार

- **खादी फैशन और भारतीय संस्कृति की समृद्ध झलकियाँ** ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले **'यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो'** के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण होंगी। आगंतुकों को ब्रज, पूर्वांचल, अवध, पश्चिमांचल, रोहिलखंड और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों की विविध परंपराओं का अनुभव मिलेगा। वियतनाम एक भागीदार देश के रूप में भाग ले रहा है।
- ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) के अनुसार, 5,765 चार्जिंग स्टेशनों के साथ, कर्नाटक में देश में सबसे ज़्यादा सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन हैं। इनमें से लगभग 85% स्टेशन (4,462) बेंगलुरु शहरी जिले में हैं।
  - बीईई के आंकड़ों से पता चलता है कि सूची में कर्नाटक, महाराष्ट्र (3,728 स्टेशन), उत्तर प्रदेश (1,989 स्टेशन) और दिल्ली (1,941 स्टेशन) से आगे है।

चर्चित व्यक्तित्व - नियुक्ति

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गोविंद मोहन	वह अजय कुमार भल्ला की जगह **केंद्रीय गृह सचिव** का पद संभालेंगे। सिक्किम कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी मोहन इससे पहले **केंद्रीय संस्कृति सचिव** के पद पर कार्यरत थे और 'आजादी का अमृत महोत्सव' और 'हर घर तिरंगा' जैसी प्रमुख पहलों की देखरेख कर चुके हैं।	

महत्वपूर्ण दिन/तारीख

23 अगस्त	**राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस** 	23 अगस्त 2024 को भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया, जो **चंद्रयान-3 मिशन के विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग का प्रतीक** था। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 का विषय है **"चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना: भारत की अंतरिक्ष गाथा",** जो समाज पर अंतरिक्ष अन्वेषण के व्यापक प्रभाव पर प्रकाश डालता है और इस बात पर बल देता है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रगति कैसे पृथ्वी पर जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकती है।

अन्य राज्यों से महत्वपूर्ण समसामयिकी

महाराष्ट्र	महाराष्ट्र ने सौर ग्राम योजना शुरू की है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य **100 गांवों को 100% सौर ऊर्जा से बिजली उपलब्ध कराना** है। सतारा जिले का मन्याचीवाड़ी इस योजना से लाभान्वित होने वाला पहला गांव है, जिससे यह राज्य का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है।

वैश्विक समसामयिकी

श्रीलंका	इसने विश्व का सबसे लम्बा डाक टिकट जारी किया है, जिसकी लम्बाई 205 मिमी है। यह टिकट कैंडी के ऐतिहासिक **श्री दलदा पेराहेरा** का प्रतीक है और इसका मूल्य 500 रुपये है। कैंडी एसाला पेराहेरा, जिसे दांतों का त्योहार भी कहा जाता है, श्रीलंका के कैंडी में जुलाई और अगस्त (एस्ला माह) में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है।

OOOO